(c) There will be no retrenchment.

(d) No Commission -was appointed as such to suggest administrative changes in DDA. Sarkaria Commission is to go into the entire set-up of Delhi.

(e) It is proposed to be implemented in about 6 months time. At the Snoment' there is[1] no proposal to open new registration.

(f) The houses under construction shall be completed by the year 1988-*89* and 89-90. The number of registrants awaiting allotment under various housing schemes are as under: —

GENERAL HOUSING SCHEME EPS—1985

MIG	*JUG*	*'JANTA*	*TOTAL*
2695	1396	279	4370

NEW PATTERN SCHEME 1979 (HUDCO)

30486	48645	32916	1/12/047

SELF ■ FINANCING SCHEME

23950	23,950

श्रम मंत्रालय में हिन्दी भाषा का प्रसार

450. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णत: अवहेलना करते हुए अंग्रेजी रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिंदी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और यहां भी टेलेक्स मशीनें लगायी गई है वहां से एक भी तार हिंदी में नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकण यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिए थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं । श्रम मंत्रालय में, पिछले एक वर्ष के दौरान, कोई भी अंग्रेजी रोमन कम्प्यूटरों/टेलेक्स मशीनों/टेलीप्रिंटरों की खरीद नहीं की गई थी । इन्हें बहुत पहले खरीदा गया था ।

जहां तक तारों का संबंध है, 31-12-87 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान "क" क्षेत्रों में 21% तार हिन्दी में भेजे गए थे ।

(ख) जी, नहीं । श्रम मंत्रालय में, 13 देवनागरी टाइप-राइटर, 19 हिंदी टंकक और 13 हिन्दी आशुलिपिक हैं ।

(ग) रोमन टाइपराइटरों को देव-नागरी में बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने के लिए अनुनय प्रयास तेज किए जा रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

451. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी